

व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि - बुनाई

द्वारा

जय काली- स्वयं सहायता समूह



एसएचजी/सीआईजी नाम	::	जय काली
वी एफ डी एस नाम	::	डूबलिंग
श्रेणी	::	पूह
विभाजन	::	किन्नौर

इसके तहत तैयार:



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1.	परिचय	3-4
2.	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	6
3.	लाभार्थियों का विवरण	6-7
4.	गांव का भौगोलिक विवरण:	7
5.	प्रबंध	7-8
6.	प्राथमिक कार्य योजना	8
7.	ग्राहकों	8
8.	केंद्र का लक्ष्य	8
9.	इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण	8
10.	स्वोट अनालिसिस	8-9
11.	मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण	9-10
12.	महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि	10-11
13.	लाभ का बंटवारा	11
14.	धन के स्रोत और खरीद	12
15.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	12
16.	ऋण चुकौती अनुसूची	12
17.	निगरानी विधि	13
18.	टिप्पणी	13
	समूह के सदस्यों की तस्वीरें	13-16

1. परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है और पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इसकी विशेषता कई चोटियों और व्यापक नदी प्रणाली की विशेषता वाले चरम परिदृश्य हैं। हिमाचल प्रदेश को "भगवान की भूमि" के रूप में जाना जाता है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है।

राज्य में विविध पारिस्थितिकी तंत्र, नदियाँ और घाटियाँ हैं, और इसकी आबादी 7.5 मिलियन है और यह शिवालिक की तलहटी से लेकर मध्य पहाड़ियों (MSL से 300 - 6816 मीट्रिक टन ऊपर), ऊँची पहाड़ियों और ऊपरी हिमालय के ठंडे शुष्क क्षेत्रों तक 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह घाटियों में फैला हुआ है, जहाँ से कई बारहमासी नदियाँ बहती हैं। राज्य की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि, बागवानी, जलविद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं।

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और किन्नौर राज्य के बारह प्रशासनिक जिलों में से एक है। किन्नौर जिला तीन प्रशासनिक उप-विभागों में विभाजित है, जैसे कल्पा, पूह (भाबानगर) और पूह और इसमें छह तहसील हैं। जिले का मुख्यालय रिकांग पियो में स्थित है। यह लाहुल और स्पीति के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 84121 है।

किन्नौर जिला कभी निषिद्ध क्षेत्र था, लेकिन अब यह साहसी और साहसी साधकों के लिए एक खजाना बन गया है। भगवान शिव का निवास किन्नर कैलाश पर्वत कल्पा से देखा जा सकता है। इसके अलावा नाको गांव में प्राचीन काल है। निचले किन्नौर में हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव है, जबकि उनकी आस्था प्रणालियों में बौद्ध धर्म के निशान हैं, और ऊपरी इलाकों में बौद्ध धर्म का बोलबाला है और दोनों धर्म सद्भाव में सह-अस्तित्व में हैं। किन्नौर जिला अपने सूखे मेवों जैसे चिलगोजा, खुबानी और बादाम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेब की खेती ने भी गति पकड़ी है और अब किन्नौर जिले के सेब राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

स्वेटर और कार्डिगन बुनने के साथ-साथ मोजे, मफलर, स्कार्फ, टोपी, दस्ताने आदि बुनना मुख्य रूप

से ग्रामीण भारत की महिलाओं के बीच एक आम घरेलू गतिविधि है। अधिकांश महिलाएं इस IGA से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे अपने खाली समय में और साथ ही घर के अन्य कामों के साथ इसे खुशी-खुशी करती हैं। इस SHG की महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने इस गतिविधि को IGA के रूप में चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और मुश्किल समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। विभिन्न आयु वर्ग की 10 महिलाओं का एक समूह JICA परियोजना के तहत एक SHG बनाने के लिए एक साथ आया और एक व्यवसाय योजना तैयार करने का फैसला किया, जो उन्हें इस IGA को सामूहिक रूप से लेने और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सके।

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

3.1	एसएचजी/सीआईजी नाम	::	जय काली
3.2	वीएफडीएस	::	डूबलिंग
3.3	श्रेणी	::	पूह
3.4	विभाजन	::	किन्नौर
3.5	गाँव	::	डबलिंग (तितांग)
3.6	अवरोध पैदा करना	::	पूह
3.7	ज़िला	::	किन्नौर
3.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	10- महिलाएं
3.9	गठन की तिथि	::	6/04/2022
3.10	बैंक खाता सं.	::	25810107217
3.11	बैंक विवरण	::	एसबीआई पूह
3.12	एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत	::	100/- (बैठक होने वाली है) आयोजित कभी 6 वां दिन माह का)
3.13	कुल बचत	::	2000
3.14	कुल अंतर-ऋण	::	
3.15	नकद क्रेडिट सीमा	::	--
3.16	पुनर्भुगतान स्थिति	::	--

3. लाभार्थियों विवरण:

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद का नाम	आयु	वर्ग	आय स्रोत	संपर्क नंबर।
1.	श्रीमती विमला देवी	श्री सम्पा दोरजे	प्रधान	39	अनुसूचित जनजाति	कृषि	9015175696
2.	श्रीमती निकिता	श्री अर्जुन सिंह	सचिव	21	अनुसूचित जनजाति	कृषि	9015067242
3.	श्रीमती मंगसा देवी	श्री चुंगू छेरिंग	सदस्य	72	अनुसूचित जनजाति	कृषि	7018014480
4.	श्रीमती कमलेश कुमारी	श्री ठाकुरसिंह	सदस्य	53	अनुसूचित जनजाति	कृषि	9015199278
5.	श्रीमती रूपा देवी	श्री दावा	सदस्य	41	अनुसूचित जनजाति	कृषि	9015186794
6.	श्रीमती पूजा	श्री छेरिंग दोरजे	सदस्य	39	अनुसूचित जनजाति	कृषि	8580925848
7.	श्रीमती वीना कुमारी	श्री रिनजिंग	सदस्य	38	अनुसूचित जनजाति	कृषि	8544725781
8.	श्रीमती खांडो	श्री सूरज की पत्नी	सदस्य	27	अनुसूचित जनजाति	कृषि	9015314133
9.	श्रीमती शालू देवी	श्री नीमा छेरिंग	सदस्य	31	अनुसूचित जनजाति	कृषि	7876703357
10.	श्रीमती जागमो	श्री श्राद तंजिन	सदस्य	49	अनुसूचित जनजाति	कृषि	7807380671

4. गांव का भौगोलिक विवरण:

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	69किमी
4.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	एनएच 5 से 0.5 किमी
4.3	स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	::	पूह-10 किमी, रिकांगपिओ-69 किमी और रामपुर 169 किमी
4.4	मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी	::	पूह-10 किमी, रिकांगपिओ 69 किमी और रामपुर 169 किमी
4.5	मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी	::	रिकांगपिओ- 69 किमी और रामपुर 169किमी
4.6	नाम का स्थान/स्थान कहाँ उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा	::	पूह-10 किमी, रिकांगपिओ-69 किमी और रामपुर 169 किमी

5. प्रबंधन

जय काली द्वारा संचालित बुनाई केंद्र में 10 महिला सदस्य हैं और उनके पास साझा बुनाई मशीनें होंगी (तीन नं. सरल और दो नं. कार्ड मशीन कुल 5 नं.) और अपनी योजना को क्रियान्वित करने और सामूहिक रूप से काम करने के लिए गांव में एक कमरा किराये पर लेंगे। केंद्र में वास्तविक काम शुरू होने से पहले सभी सदस्यों को कुछ पेशेवर प्रशिक्षकों के तहत बुनाई में प्रशिक्षण देने के लिए एक अल्पकालिक कैप्सूल कोर्स कराया जाएगा।

6. प्राथमिक कार्य योजना

इस स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पास इस IGA के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और समूह के भीतर सावधानीपूर्वक और विचारशील चर्चा के बाद अतिरिक्त आय के लिए इस गतिविधि को अपनाने का फैसला किया। सदस्य इस गतिविधि को अलग-अलग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस गतिविधि को थोड़े बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए हाथ मिलाया है। सदस्यों के बीच श्रम का विभाजन सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति IGA को मजबूत करने में योगदान दे सके और परिणामस्वरूप उनकी जेब में अतिरिक्त पैसा आए।

7. ग्राहक

हमारे केंद्र के प्राथमिक ग्राहक ज्यादातर डबलिंग गांव के आसपास के स्थानीय लोग होंगे ,तितांग, पूह लेकिन बाद में इस व्यवसाय को आस-पास के छोटे कस्बों में भी फैलाया जा सकता है।

8. केंद्र का लक्ष्य

केंद्र का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से डुबलिंग टिटैंग, पूह गांव के निवासियों और आसपास के गांवों के सभी अन्य निवासियों को अद्वितीय आधुनिक और उच्च श्रेणी की बुनाई सेवा प्रदान करना है।

यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने परिचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सबसे प्रतिष्ठित बुनाई केंद्र बन जाएगा।

9. इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण

इस SHG के सदस्यों के पिछले अनुभव के कारण जो पहले से ही यहाँ-वहाँ यही काम कर रहे हैं, इस IGA को चुना गया है और इसलिए SHG इस व्यवसाय को शुरू कर रहा है। यह विभिन्न सदस्यों के कौशल को संयोजित करने और अधिक आजीविका कमाने के लिए उनकी गतिविधि को बढ़ाने का एक प्रयास है।

10. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

❖ ताकत

- कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
- कच्चा माल आस-पास के बाजारों में आसानी से उपलब्ध
- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसानी
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है

❖ कमजोरी

- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ अवसर

- अच्छे उत्पादों की बढ़ती मांग

❖ खतरे/जोखिम

- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता

11. मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण

पारंपरिक बुनाई के साथ-साथ यांत्रिक बुनाई भी साथ-साथ चलेगी ताकि विपणन के लिए एक मूल्यवान उत्पाद उपलब्ध कराया जा सके और इसे गुणवत्ता और मूल्य टैग दोनों में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। लक्षित क्षेत्र में मांग के आधार पर कुछ वस्तुओं का उत्पादन पारंपरिक तरीके से और कुछ का यांत्रिक तरीके से किया जाएगा। निम्नलिखित मशीनरी और उपकरणों को खरीदने की आवश्यकता है

एक	पूंजीगत लागत			
क्रमांक	मशीनरी का विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि
1.	पंच कार्ड बुनाई मशीन	04	30000	120000
2.	बुनाई डिजाइन पुस्तक	1	1500	1500
3.	काम करने की मेज \$ स्टूल	5	2000	8000
कुल पूंजी लागत				129500

बी	आवर्ती लागत			
क्रमांक	विवरण	इकाई	दर	मात्रा
1.	कमरे का किराया	प्रति महीने	2000	2000
2.	पानी और बिजली	प्रति महीने	1000	1000
3.	बुनाई का धागा अलग रंग और गुणवत्ता	प्रति माह एल/एस	95000	95000
4.	चिकनाई तेल & पिपेट	प्रति महीने	1400	1400
5.	टूट फूट	प्रति महीने एल/एस	1500	1500
कुल आवर्ती लागत				100900

12. महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि

चूंकि यह SHG में उनके नियमित घरेलू काम के अलावा एक अतिरिक्त गतिविधि है, इसलिए परिणाम प्रत्येक सदस्य के काम के घंटों के अनुपात में होगा। हमेशा शुरुआत में उत्पादन को रूढ़िवादी पक्ष पर रखना बेहतर होता है जिसे समय बीतने और कार्य अनुभव के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि प्रत्येक सदस्य अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के रूप में प्रतिदिन एक वस्तु का उत्पादन करेगा और प्रतिदिन 14 वस्तुओं को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस उत्पादन दर को ध्यान में रखते हुए एक महीने में लगभग 400 तैयार वस्तुएं बिक्री के लिए तैयार होंगी। शुरुआत के तौर पर अगर औसत दर 600 रुपये प्रति वस्तु मानी जाए तो प्रति माह कुल आय इस प्रकार होगी:

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान (75%)	एसएचजी योगदान (25%)
कुल पूंजी लागत	129500	97125	32375
आवर्ती लागत			
पूंजीगत लागत पर 10% मूल्यहास/माह	2300	-	-
प्रति माह अन्य व्यय	100900	-शून्य-	100900
कुल	1,01,835		100,900

एक माह में कुल बिक्री $(600 \times 400) = 240000$

पहले महीने में कुल व्यय $(129500 + 103200) = 262700$

हालाँकि, 97125 रुपये की राशि परियोजना सहायता है इसलिए गणना के उद्देश्य से इस राशि को व्यय कॉलम से सुरक्षित रूप से घटाया जा सकता है और शुद्ध आय को फिर से फिर से डाला जा सकता है। इसके अलावा SHG के सदस्य सामूहिक रूप से काम करेंगे इसलिए उनकी मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा गया है। महीने के अंत में शुद्ध आय को निम्नानुसार फिर से डाला जाता है

पूंजीगत लागत		
विवरण	मात्रा	एसएचजी योगदान
पूंजीगत लागत	127500	32375
<u>आवर्ती व्यय</u>		
में) 10% मूल्यहास प्रति माह पूंजीगत लागत	2300	
में) अन्य सामग्री लागत आदि पर व्यय	100900	
कुल	1,03,200	
कुल लागत	$32375 + 103200 = 1,35,575$	
पहले महीने में कुल बिक्री	240000	
शुद्ध लाभ	1,14,840	

13. लाभ का बंटवारा

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि प्रथम माह में प्रत्येक सदस्य को 6000 रुपये आय के रूप में दिए जाएंगे तथा शेष 34,850 रुपये का लाभ उनके बैंक खाते में आपातकालीन आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

14. समूह में निधि प्रवाह:

क्रमांक।	विवरण	कुल राशि (₹.)	परियोजना योगदान	स्वयं सहायता समूह योगदान
1	कुल पूंजी लागत	129500	97125	32375
2	कुल आवर्ती लागत	1,00,900	0	1,00,900
3	प्रशिक्षण	71000	71000	0
	कुल परिव्यय	301400	168125	133275

टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत -कुल पूंजीगत लागत का 75% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा
- आवर्ती लागत -संपूर्ण लागत एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन की जाएगी।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -परियोजना द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत

15. धन के स्रोत और खरीद:

परियोजना समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। • स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि परिक्रामी निधि के रूप में जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमताभवन/कौशल उन्नयन लागत।	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मशीनों की खरीद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
------------------	---	--

एसएचजी योगदान	पूँजीगत लागत का 25% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा।	
	आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन ---

- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

17. ऋण चुकौती अनुसूची-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

18. निगरानी विधि -

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्यवाई का सुझाव देगी।

- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्यवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

19. टिप्पणी

समूह सदस्यों की तस्वीरें-



समूह सहमति पत्र

आज दिनांक 13-06-2023 जय काली स्वयं सहायता समूह डुबलिंग में बैठक हुई यह बैठक प्रधान श्रीमति बिमला देवी के अध्यक्षता में हुई। आज बैठक में यह चर्चा की सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि जाईका वन विभाग की तरफ से जो धन राशि मिलेगी उसका उपयोग बुनाई सिखने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सदस्यों की सहमती प्रकट की है इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

प्रधान

जय काली स्वयं सहायता समूह
डुबलिंग, जिला किन्नौर हि०प्र०

समूह के प्रधान का हस्ताक्षर

बिमला देवी

सचिव

जय काली स्वयं सहायता समूह
डुबलिंग, जिला किन्नौर हि०प्र०

समूह के सचिव का हस्ताक्षर

NIRI-10

Memorandum of Understanding

Between

The KINNAUR..... Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO KINNAUR for Participatory Forest Management.

Whereas

- The KINNAUR..... Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of KINNAUR village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district KINNAUR and Forest Division KINNAUR Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called "EC"),
- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called "Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division
- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;
- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The KINNAUR..... Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. Purpose of the Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding (hereinafter called "Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

Responsibilities of the Society

- 2.1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.
- 2.2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.
- 2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.
- 2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.
- 2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.
- 2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.
- 2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.
- 2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.
- 2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.
- 2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.
- 2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.
- 2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the

- Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.
- 2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.
 - 2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).
 - 2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

- 3.1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.
- 3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)
- 3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.
- 3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.
- 3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.
- 3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

- 4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.
- 4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.
- 4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.
- 4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..will be credited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan) of VFDS/BMC (Sub-Committee). In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.

5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years. the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;

vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling,

whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,

6. Monitoring & Evaluation

6.1 Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

6.2. The EC of VFDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

- 6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.
- 6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for that activity.
- 6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I Teet. Ram President, Sarling Joint VFDS/BMC

(Sub-committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

(Name and Signature of the President)
On behalf of VFDS/ BMC (Sub-committee)

प्रधान ज्यका
ग्राम वन विकास समिति डुबलिंग
सेठ पूह, जिला किन्नौर (हि.प्र.प्र.०)

Divisional Forest Officer
Kinnaur Forest Officer
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

1. Kamlesh Kumari
2. bimla Devi
3. Chwang Tolpey
4. Karan Mogi

1. Sh. Sohan Singh, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer
Pooh Range

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of Kinnaur Forest Department.

cfA

31/5/2024

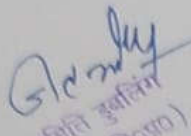


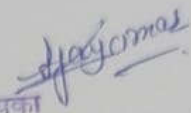
Kinnaur Forest Division
At R/Peo

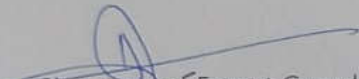
Business Plan Approval by VFDS & DMU

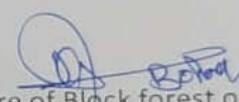
Jai bali Self help group will undertake the knitting
As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh
Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan
of amount (Rs.) 3,01,400 has been submitted by this group on dated -----
----- and this business plan has been approved by ----- VFDS. Business
Plan with SHG resolutions being submitted to DMU through FTU for further action, please.

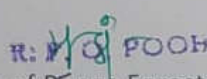
Thankyou


ग्राम वन विकास समिति डुबलिंग
तेह्रपूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)
Signature of VFDS Pradhan


सचिव ज्यका
ग्राम वन विकास समिति डुबलिंग
तेह्रपूह, जिला किन्नौर (हि०प्र०)
Signature of VFDS Secretary


Signature of Forest Guard


Signature of Block forest officer
Block Forest Officer
Pooch Distt Kinnaur H.P


Signature of Range Forest officer


Approved
DMU -cum-
Deputy conservator forests,
Kinnaur Division at R/Peo

Resolution –cum-group consensus form

It is decided in the general house meeting of the Self Help Group.....Jai Kali..... Held on
.....at.....Dusling..... that our self help group will undertake the
.....knitting.....as livelihood income generation activity under the project for
improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted.)

विमला देवी
Signature of Group Pradhan
जय काली स्वयं सहायता समूह
दुबलिंग, जिला किन्नौर हि०प्र०

सवित्री विकी
जय काली स्वयं सहायता समूह
दुबलिंग, जिला किन्नौर हि०प्र०
Signature of Group Secreta